To,

E-Mail

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Ref. No. : 1502/Mines/2024 **Date :** 29-10-2024

Subject: Submission of response report on behalf of District Magistrate, Fatehpur in compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 959/2024 Lav Mishra Versus State of U.P. & Ors.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order passed on dated 13.09.2024 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 959/2024 Lav Mishra Versus State of U.P. & Ors., the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your's Sincerely

(Ravindra Singh)
District Magistrate,
Fatehpur

Copy to:-

1. Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change, U.P. Government, Lucknow.
2. Director, Mining and Geology, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow.
4. Shri Ankit Verma, Advocate on Record, Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi for perusal and necessary action please.

District Magistrate,
Fatehpur

DISTRICT MAGISTRATE, FATEHPUR

To,

E-Mail

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Ref. No. : 1502/Mines/2024 **Date :** 29-10-2024

Subject: Submission of response report on behalf of District Magistrate, Fatehpur in compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 959/2024 Lav Mishra Versus State of U.P. & Ors.

Sir,

With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order passed on dated 13.09.2024 by Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 959/2024 Lav Mishra Versus State of U.P. & Ors., the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your's Sincerely

(Ravindra Singh)
District Magistrate,
Fatehpur

Copy to:-

1. Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change, U.P. Government, Lucknow.
2. Director, Mining and Geology, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow.
4. Shri Ankit Verma, Advocate on Record, Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi for perusal and necessary action please.

District Magistrate,
Fatehpur

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय आदेश संख्या जी 00946/ओ0ए0 नं0 959/2024/एन0जी0टी0/24–25, दिनांक 30.09.2024 के द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 13.09.2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

1. The Original Application has been registered under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') in exercise of suo motu jurisdiction in view of the law laid down by Supreme Court in Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401, on a letter petition dated 21.11.2023 received from Lav Mishra, an environment activist resident of 85, Indira Nagar Lucknow, UP.
2. The complainant has stated that R.B. Enterprises, under the proprietorship of Virender Singh s/o Shri Ram Kishore Singh r/o AtarraChungi, Chowki Kushwaha Nagar, Tehsil and District Banda, is engaged in illegal sand mining under Lalulli, District Fatehpur in violation of conditions of Environmental Clearance and Consent and thereby causing damage to environment. Mining activities have been carried out using heavy machines which is prohibited under the conditions of Environmental Clearance. Transportation of sand is by open vehicles and 2 that too with overloaded trucks. The mining is also being carried out day and night floating condition Environmental Clearance and Consent.
3. Considering the above allegations, prima-facie, we are of the view that substantial question relating to environment has arisen out of the implementation of Enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010, but before proceedings in the matter, we find if appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Fatehpur and Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB').
4. District Magistrate, Fatehpur shall be nodal authority for compliance and coordination of this order.
5. The said Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within six weeks.
6. Further, we find it appropriate to implead following as Respondents:
    1. State of UP through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, 1st Floor, Room No. 110, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow.
    2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, 1st Floor, Room No. 110, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow, through Additional Chief Secretary.

3. Director, Mining and Geology, Government of Uttar Pradesh, 1st Floor, Room No. 110, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow.
4. District Magistrate, Fatehpur
5. Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, 2nd Floor, 4, Kalpi Road, Kanpur – 208012.

7. Registry is directed to serve the above Respondents and they may file responses within two weeks after receipt of the notice.

8. List on 05-11-2024

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के क्रम में जिलाधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय आदेश संख्या जी 00946/ ओ0ए0 नं0 959/2024/एन0जी0टी0/24–25, दिनांक 30.09.2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित की गयी **(संलग्नक–01)**। जांच समिति में निम्नलिखित अधिकारी नामित किये गये है :–

1. उप जिलाधिकारी, सदर, फतेहपुर
2. खान अधिकारी, फतेहपुर
3. सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा गठित जांच समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 16.10.2024 को स्थलीय जांच किया गया। जांच के समय निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :–

1. मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर स्थित ग्राम उरौली के बालू/मोरम खण्ड सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69, 83 से 91तक, 108से 112तक, 115से 121तक, 141से 149तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586 कुल रकबा 50.00हे0 दिनांक 07.05.2022 से दिनांक 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया था।
2. उक्त बालू खनन पट्टे को राज्य स्तरीय पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, उ0प्र0 के EC Identification No.-EC22B001UP163690, File no-6934-5978, Date 02/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है, जिसकी प्रति **संलग्नक–2** के रूप में संलग्न है।
3. उक्त खनन पट्टे को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या 175629/ UPPCB/Allahabad (UPPCBRO)/CTO/both/FATEHPUR/2023, Dated 16/02/2023 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 16.02.2023 से दिनांक 31.12.2024 तक है, जिसकी प्रति **संलग्नक–3** के रूप में संलग्न है।

4. मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अतरा चुंगी चौकी, कुशदाहा नगर जिला बाँदा, पार्टनर श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतरा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बाँदा पट्टाधारक मोरम खण्ड सं0–उरौली के द्वारा खनन पट्टा संचालन अवधि के दौरान उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली–1963 यथासंशोधित नियमावली–2021 के नियम–42 (ज), 60(6), 3, 58, 36(1), (2) एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन पाया गया।

5. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42 (ज)(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टेदार नदी तल मे तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र मे नही किया जायेगा : प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जलधारा मे सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नही किया जायेगा।"

6. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(4) में यह प्राविधानित है कि "नियम 42 (ज) के अधीन उपबन्धित उप बन्धों के अनुसार जल धारा मे सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिए दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने मे विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी"।

7. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(6) में यह प्राविधानित है कि "जहॉ पट्टाधारक विहित लोडिंग सन्नियमों की पुष्टि करने मे विफल हो जाये, वहॉ ऐसे प्रत्येक चूँक की दशा मे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रु0–25,000/–की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। उक्त शास्ति को जमा करने मे विफल रहने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से कटौती कर ली जायेगी"।

8. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन मानचित्र पर कोर्डिनेटस चिन्हांकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमां चिन्ह को और खम्भे को परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति मे रखेगा, जो पट्टाविलेख से संलग्न नक्शे मे दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो"।

9. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(2) में यह प्राविधानित है कि "खनन पट्टाधारक, जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हे0 से अधिक है, परिवहन की निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य 04 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेटपर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गय ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पड़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी, और उसका समुचित रूप से रखरखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप मे अनुरक्षित रहेगा। पट्टेधारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0 आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा। और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।

10. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(3) में यह प्राविधानित है कि "यदि पट्टाधारक, नियम 36 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्गृहीत की जायेगी। ऐसी उद्गृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा मे उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा"।

11. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 में यह प्राविधानित है कि "कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र मे किसी ऐसे उप खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की निबन्धन और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियाएं नही कर सकेगा।"

12. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–58 में यह प्राविधानित है कि "जो कोई नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों मे से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पॉच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रूपये एवं अधिकतम पॉच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।"

13. उपरोक्त उल्लंघन के दृष्टिगत पट्टाधारक को प्रत्येक जॉच मे पाये गये उल्लंघन के प्रत्येक अवसर पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिसें निर्गत की गईं और यथा उचित उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुये गुण–दोष के आधार पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली के नियम–59 मे प्रदत्त अधिकारों के तहत मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में स्वीकृत उपरोक्त बालू/मोरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को आदेश सं0–1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 **(संलग्नक–4)** द्वारा निरस्त करते हुये निम्न आदेश पारित किये गये :–

(i) तालिका–1 मे उल्लिखित शास्ति सहित कुल बकाया धनराशि रु0–1,02,34,420/–, तालिका–2 में उल्लिखित खनन पट्टा किश्त की बकाया धनराशि रु0–2,42,79,575/– तालिका–4 मे उल्लिखित यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल पर वाल्यूम मिसमैच एवं बिदआउट ई–एम0एम0–11 के आनलाइन नोटिस की धनराशि रु0–1,41,06,323/–कुल धनराशि रु0–4,86,20,318/–को जमा प्रतिभूति की धनराशि 1,79,06,250/– में समायोजित किया जाता है। पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि समायोजन के उपरान्त अवशेष बकाया धनराशि रु0–3,07,14,068/–आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर निर्धारित लेखा शीर्षक "0853"/राजकोष के एकेवीकोड के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ii) डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रु0–1,67,74,575/–जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास फतेहपुर के खाता संख्या–37171070081 आई0एफ0एस0सी0 कोड–SBIN0000076 मे, तथा देय टी0सी0एस0 की धनराशि रु0–रु0–33,54,915/–को निर्धारित टैन नं0–ALDD00887F में) आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर जमा कराकर जमा रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई देयता बनती है, तो उसकी वसूली पृथक से की जायेगी।

(iii) पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त अधिरोपित धनराशि नियत समय मे जमा नही करने पर नियमानुसार बकाया धनराशि की वसूली समस्त भागीदारों से भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल किये जाने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

14. जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश सं0–1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम–उरौली, तहसील–फतेहपुर, जनपद–फतेहपुर के पक्ष में स्वीकृत बालू/मौरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 59 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निरस्त किया गया है। उक्त माईनिंग प्रोजेक्ट को निर्गत सशर्त सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक 16.02.2023 के विशिष्ट शर्त संख्या 03 में निम्नवत् उल्लेख किया गया था :–

If the lease agreement expires prior to 31.12.2024, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त सन्दर्भित सैण्ड माईनिंग प्रोजेक्ट को निर्गत सशर्त सहमति (जल एवं वायु) दिनांक 16.02.2023 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या एच 18875/सी–2/वायु–356/24, दिनांक 21.10.2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया गया है तथा पट्टाधारक को निर्देशित किया गया है कि उक्त स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के खनन कार्य न किया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 21.10.2024 द्वारा सहमति आदेश को निष्प्रभावी किये जाने के पत्र की प्रति **संलग्नक–05** के रूप में संलग्न है।

15. उक्त आदेश सं0–1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 से क्षुब्ध होकर याची मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे रिट याचिका सी–26843/2024 मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गईहै।

16. उक्त याचिका सं0–26843/2024 मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 20.08.2024 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

"1. Heard counsel for the petitioner and learned Standing Counsel.

2. Learned counsel for the petitioner submitted that the controversy in the instant writ petition is squarely covered by the order which has been passed in a similar matter, copy of which has been found at page 96 of the paper book and that an identical order be passed in this petition.

3. Learned Standing Counsel has no objection to this prayer.

4. The present petition has been filed challenging the order dated 11.7.2024 issued by the respondent No. 3, so far as it relates to demand of DMF amount.

5. It has been stated by the petitioner and the said fact has not been denied by the learned Standing Counsel that the issue regarding liability to pay the DMF amount, i.e., the amount due to the District Mineral Foundation Trust has already been concluded by a Division Bench judgment of this Court dated 15.11.2017 passed in Writ - C No. 54052 of 2017 against which a Special Leave to Appeal (C) No. 35161 of 2017 has been filed before the Supreme Court.

6. It has been stated in the petition that in the aforesaid special leave to appeal, the Supreme court has passed an interim order permitting the petitioner to deposit the statutory royalty and furnish a bank guarantee of the balance amount of royalty claimed by the respondent and the demand notices shall remain stayed on the petitioner furnishing the bank guarantee.

7. A bunch of writ petitions in which the leading case was Writ - C No. 16647 of 2020 (M/s Hardik Distributors Pvt. Ltd. vs. State of U.P. and others), this Court passed an order dated 17.05.2023 disposing of the aforesaid petitions.

8. The operative part of the order dated 17.05.2023, passed by this Court is reproduced below:

"4. We find that this batch of writ petitions are pending in this court from last several years. Therefore, we propose to dispose of all these writ petitions, providing as under:

(i) All the writ petitions are disposed of in terms of the Division Bench judgment of this court dated 15.11.2017 in Writ-C No.54052 of 2017, which shall be subject to the final decision of Hon'ble Supreme Court in the Petition for Special Leave to Appeal (C) No.35161 of 2017 (Chandra Bhan Singh vs. The State of Uttar Pradesh and others) and in the event, the aforesaid Petition for Special Leave to Appeal is allowed or any relief is granted by Hon'ble Supreme Court, then the respondents shall extend the relief so granted to all the petitioners of this batch of writ petitions and the concerned respondents shall also pass appropriate orders in the matter of the petitioners in terms of the final decision of Hon'ble Supreme Court including directions for release of Bank Guarantees, if any.

(ii) The benefit of interim order granted by Hon'ble Supreme Court as afore quoted, shall continue to be available to the petitioners till the aforesaid Petition for Special Leave to Appeal (C) No.35161 of 2017 is finally decided by Hon'ble Supreme Court."

1. As the issues raised in the present petition are the same as the issues raised in Writ - C No. 16647 of 2020, this petition is also disposed of in terms of the order dated 17.05.2023 passed in Writ - C No. 16647 of 2020.

2. 10. It is, however, clarified that this order does not apply in so far as demand of TCS or any other dues indicated in the impugned order dated 11.7.2024 is concerned, especially because no relief in its regard has been sought in the writ petition.

17. उक्त के अनुपालन में वांछित अनुदेश मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कार्यालय पत्र सं0–1254/खनिज/रिट/2024 दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये।

18. उक्त के अतिरिक्त एक अन्य याचिका सं0–30668/2024 मेसर्स आर0बी0 इण्टरप्राइजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक 12.09.2024 को निम्न आदेश पारित किये हैं :–

"One of the submissions made by Shri Shashi Nandan, learned Senior Advocate is that a number of reasons have been assigned in the impugned order for cancelling of the lease granted to the petitioner. However, only one show cause notice was served which was dated 27.6.2023. As regards the other allegations, there was no material.

2. Learned Standing Counsel is directed to obtain instructions in the matter."

19. उक्त के अनुपालन में वांछित अनुदेश मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कार्यालय पत्र सं0–1341/खनिज/रिट/2024 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से प्रेषित किये गये।

20. जनपद फतेहपुर के तहसील सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम उरौली की गाटा संख्या–64 से 69, 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586रकबा 50.00 हे0 बालू/मोरम खण्ड सं0–उरौली का स्थलीय निरीक्षण स्वीकृत/निष्पादित खनन पट्टा अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित जियो कोर्डिनेट्स के तहत दिनांक 16.10.2024 को किया गया। जियो कोर्डिनेट्स निम्नवत् हैं :–

उत्तर–	ग्राम उरौली का शेष भाग	
दक्षिण–	यमुना नदी का शेष भाग	
पूर्व–	ग्राम सीमा दसौली	
पश्चिम–	सीमा ग्राम अढ़ावल	
बिन्दु	**अक्षांश**	**देशान्तर**
(A)	N-25°.48.573'	E-80°.28.624'
(A1)	N-25°.48.440'	E-80°.28.780'
(A2)	N-25°.48.273'	E-80°.28.969'
(A3)	N-25°.48.129'	E-80°.29.166'
(A4)	N-25°.48.924'	E-80°.29.447'
B	N-25°.47.705'	E-80°.29.835'
C	N-25°.47.622'	E-80°.29.775'
C1	N-25°.47.842'	E-80°.29.386'
C2	N-25°.48.055'	E-80°.29.087'
C3	N-25°.48.207'	E-80°.28.880'
C4	N-25°.48.363'	E-80°.28.693'
D	N-25°.48.499'	E-80°.28.529'

21. निरीक्षण के दौरान क्षेत्र सूखा एवं समतल पाया गया। खनन पट्टा क्षेत्र एवं क्षेत्र के आस–पास बालू/मोरम का खनन/परिवहन होता हुआ नही पाया गया। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं नदी की जल धारा के परिवर्तन आदि के सम्बन्ध मे भी निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि मानसून सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व की भौगोलिक स्थिति वर्तमान मे भी विद्यमान है। नदी की जलधारा आदि

मे कोई परिवर्तन नही हुआ है। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी पर्यावरणीय बदलाव एवं क्षति परिलक्षित नही हुई है।

(जॉच के समय खनन पट्टा क्षेत्र के लिए गये स्थलीय फोटोग्राफ संलग्नक–6)

22. पूर्व मे स्वीकृत बालू/मोरम खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम उरौली को कार्यालय आदेश सं0–1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र रिक्त होने के कारण शासनादेश संख्या–781/86–2020–14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से क्षेत्र को खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित कर विज्ञापन की कार्यवाही की जा रहीहै।

गठित संयुक्त समिति की आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

खान निरीक्षक,	नायब तहसीलदार,	सहायक पर्यावरण अभियन्ता,	खान अधिकारी,	उप जिलाधिकारी,
फतेहपुर	फतेहपुर	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज	फतेहपुर	फतेहपुर

जिलाधिकारी, फतेहपुर

पत्रांक 600946 /ओ०ए० नं० 959/2024/एन०जी०टी०/24-25 दिनांक 30/09/2024

फार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०सं० 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 13.09.2024 को आदेश पारित किया गया। (छायाप्रति संलग्न)। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

"........2. The complainant has stated that R.B. Enterprises, under the proprietorship of Virender Singh s/o Shri Ram Kishore Singh r/o Atarra Chungi, Chowki Kushwaha Nagar, Tehsil and District Banda, is engaged in illegal sand mining under Lalulli, District Fatehpur in violation of conditions of Environmental Clearance and Consent and thereby causing damage to environment. Mining activities have been carried out using heavy machines which is prohibited under the conditions of Environmental Clearance. Transportation of sand is by open vehicles and that too with overloaded trucks. The mining is also being carried out day and night floating condition Environmental Clearance and Consent.

3. Considering the above allegations, prima-facie, we are of the view that substantial question relating to environment has arisen out of the implementation of Enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010, but before proceedings in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Fatehpur and Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB').

4. District Magistrate, Fatehpur shall be nodal authority for compliance and coordination of this order.

5. The said Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within six weeks......"

मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश में अग्रिम सुनवाई दिनांक 05.11.2024 को नियत है। जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा जांच कर समय से तथ्यात्मक रिपोर्ट मा० अधिकरण में दाखिल किया जाना है। अतः उक्त के दृष्टिगत मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण की जॉच हेतु निम्नवत् सदस्यों की टीम का गठन किया जाता है:-

1. उप जिलाधिकारी, सदर, फतेहपुर।
2. खान अधिकारी, फतेहपुर।
3. सहायक पर्यावरण अभियंता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।

समिति के उक्त सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण की जॉच कर आख्या एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

RL Singh
(रविन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
फतेहपुर। o/c

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), फतेहपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समिति के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

RL Singh
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।
o/c

संलग्नक - (2)

ENVIRONMENTAL CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive, and Virtuous Environmental Single-Window Hub)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), Uttar Pradesh)

To,

The Proponent
M/S R.B. ENTERPRISESES
Atarra Chungi, Chowki Khushwaha Nagar, Tehsil- Banda, District- Banda - 210201

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/UP/MIN/72163/2020 dated 11 Feb 2022. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below.

1.	**EC Identification No.**	**EC22B001UP163690**
2.	**File No.**	6934-5978
3.	**Project Type**	New
4.	**Category**	B1
5.	**Project/Activity including Schedule No.**	1(a) Mining of minerals
6.	**Name of Project**	Sand/Morrum Mining Project
7.	**Name of Company/Organization**	M/S R.B. ENTERPRISESES
8.	**Location of Project**	Uttar Pradesh
9.	**TOR Date**	22 Nov 2021

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page no 2 onwards.

Date: 02/05/2022

(e-signed)
Member Secretary
Member Secretary
SEIAA - (Uttar Pradesh)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
E-Mail- doeuplko@yahoo.com, seiaaup@yahoo.com
Phone no- 0522-2300541

Reference- MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/72163/2020 & SEIAA, U.P File no- 6934-5978

Sub: Environmental Clearance is sought for Sand/Morrum Mining at Arazi No. 64 to 69, 83 to 91, 108 to 112, 115 to 121, 141 to 149, 161, 162, 167, 168, 183 to 186, 202 to 210, 234 to 245, 301 to 313, 383 to 390, 395 to 402, 409 to 412, 417 to 423, 463, 464, 587/471, 471 to 475, 499, 500, 505 to 510, 537 to 544, 561 to 565, 577 to 579, 585 & 586, Village- Urauli, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., (Leased Area- 50.0 ha.), M/S R.B. Enterprises

Dear Sir,

This is with reference to your application / letter dated 09-11-2020, 26-11-2021, 09-09-2021, 11-02-2022, 04-04-2022 on above mentioned subject. The matter was considered by SEAC in meeting held on 07-04-2022 and SEIAA in meeting held on 26-04-2022.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Environmental Research and Analysis, Lucknow to SEAC on 26-04-2022.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project –

1. The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining at Arazi No. 64 to 69, 83 to 91, 108 to 112, 115 to 121, 141 to 149, 161, 162, 167, 168, 183 to 186, 202 to 210, 234 to 245, 301 to 313, 383 to 390, 395 to 402, 409 to 412, 417 to 423, 463, 464, 587/471, 471 to 475, 499, 500, 505 to 510, 537 to 544, 561 to 565, 577 to 579, 585 & 586, Village- Urauli, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur, U.P., (Leased Area- 50.0 ha.), M/S R.B. Enterprises, Partner- Shri Birendra Singh.
2. The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. vide letter no. 312/Parya/SEIAA/5978/2021, dated 22/11/2021.
3. The public hearing was organized on 27/1/2022. Final EIA report submitted by the project proponent on 11/02/2022.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/72163/2020
2. File No. allotted by SEIAA, UP	6934-5978
3. Name of Proponent	M/s R.B. ENTERPRISES Office Address: Atarra Chungi,Chauki Kushwaha Nagar, Banda U.P. Partner- Shri Birendra Singh S/o Shri Ram Kishor Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	R/o Shastri Nagar , Atarra Chungi,Chauki Banda, UP-210001
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining Project
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No. / khand No.)	Gata No. 64 to 69, 83 to 91, 108 to 112, 115 to 121, 141 to 149, 161, 162, 167, 168, 183 to 186, 202 to 210, 234 to 245, 301 to 313, 383 to 390, 395 to 402, 409 to 412, 417 to 423, 463, 464, 587/471, 471 to 475, 499, 500, 505 to 510, 537 to 544, 561 to 565, 577 to 579, 585 & 586

7. Name of River	River Yamuna
8. Name of Village	Urauli
9. Tehsil	Fatehpur
10. District	Fatehpur (U.P)
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum Mining Project
12. Sanctioned Lease Area (in Ha.)	50.0 Ha.
13. Mineable Area (in Ha.)	40.153 ha (safety zone 9.847 ha)
14. Zero level mRL	85.0 to 86.0
15. Max. & Min mrl within lease area	Maximum mRL 95.0 mRL Minimum mrl 89.0 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	

Points	Latitude	Longitude
A	25° 48.573'N	80° 28.624'E
A1	25° 48.440'N	80° 28.780'E
A2	25° 48.273'N	80° 28.969'E
A3	25° 48.129'N	80° 29.166'E
A4	25° 47.924'N	80° 29.447'E
B	25° 47.705'N	80° 29.835'E
C	25° 47.622'N	80° 29.775'E
C1	25° 47.842'N	80° 29.386'E
C2	25° 48.055'N	80° 29.087'E
C3	25° 48.207'N	80° 28.880'E
C4	25° 48.363'N	80° 28.693'E
D	25° 48.499'N	80° 28.529'E

17. Total Geological Reserves	15,00,000 m^3
18. Total Mineable Reserves in LOI	3,75,000 m^3 per year in LOI
19. Total Proposed Production (in five year)	18,75,000 m^3
20. Proposed Production/year	3,75,000 m^3 per year
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 Year
22. Production of mine/day	NA
23. Method of Mining	Open cast, semi mechanized
24. No. of working days	250
25. Working hours/day	8 hours/day
26. No. Of workers	Approximately 105 workers
27. No. Of vehicles movement/day	120-125 Vehicles movement/day
28. Type of Land	Government Land
29. Ultimate Depth of Mining	1.0 m
30. Nearest metalled road from site	NH-232 at 3.5 km towards East direction from the project site
31. Water Requirement	

PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)
Drinking	1.15 KLD
Suppression of dust	3.0 KLD
Plantation	0.25 KLD
Others (if any)	-
Total	4.4 KLD Approx.

32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No And period of validity.	Environmental Research and Analysis, Lucknow (U.P) Certificate No. NABET/EIA/1922/RA 0200 valid up to 30/12/2022
33. Any litigation pending against the project or land in any court	NO
34. Details of 500 m Cluster Map & certificate	Letter No. 1158/30-Khanij (2020-21), Dated

issued by Mining Officer	01/10/2020
35. Details of Lease Area in approved DSR	Letter No-814/30-Khanij (2021-2022) dated 26/02/2022.
36. Proposed EMP cost	Rs 6,68,500/-
37. Proposed Total Project cost	Rs. 9,00,00,000/-
38. Length and breadth of Haul Road	250 m length and 6.0 m width
39. No. of Trees to be Planted	250
40. Monitoring Period	1/10/2020 to 31/12/2020(Post Monsoon)

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) Meeting (SEAC) held on 07-04-2022 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting dated 26-04-2022 decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 3,75,000 m^3 per year for lease area of 50 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:-

General Conditions:

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours' time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take-care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.

14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, ZilaParisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.

32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.
35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.
37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, ZilaParishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknowby e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.

48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:

1. Validity period of this EC is 5 year from the date of issue as the LoI has been issued for a period of 5 year or co-terminus with the validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier. After this period the EC will become null and void.
2. In the absence of replenishment study, keeping in mind various orders issued by Hon'ble NGT and development works in the State, initially EC will be operational for a period of one year from the date of issuance and permissible quantity and area shall be strictly limited to quantity and area mentioned in LoI or mining plan, whichever is lesser, and maximum mineable depth will be limited to as approved in the mining plan.
3. For subsequent years, Project Proponent shall submit fresh annual replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal for next three years to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC. The placing of the study report SEAC is mandatory for initial three years.
4. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
5. A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.
6. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
7. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
8. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 50,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
9. In consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepared a conservation and management plan for rejuvenation and management of water bodies having total surface area of more than 250 ha. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.
10. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance,

if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.

11. Any application for transfer of this EC, during its validity period unless it is cancelled by a competent authority, has to be necessarily accompanied with status of compliance of EC conditions duly certified by IRO, MoEFCC, GoI, Lucknow.
12. Proponent shall submit the notarized agreement/consent of competent authority/ landowner for haulage road from lease site to link road.
13. Proponent should use latest technology for water spraying (sprinklers) for mitigating dust at source points in lease area and haulage road during operation activity/vehicular movement.
14. Proposed plantation plan with area specific plant species, number of plants to be planted and place of plantation along with a proper map to be submitted.
15. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.
16. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
17. Environment management in according to environmental status and impact of the project.
18. During the school opening and closing time transportation of minerals will be restricted.
19. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
20. No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
21. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
22. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
23. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
24. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
25. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
26. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
27. Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
28. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
29. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
30. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
31. Drinking water for workers would be provided by tankers.
32. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
33. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
34. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
35. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.

36. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
37. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
38. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
39. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statuary committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
40. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
41. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
42. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
43. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05 ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05 ha, the E.C issued will stand revoked.
44. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
45. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
46. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
47. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
48. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
49. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
50. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provid adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical

examination of the workers engaged in the project shall be carried out and record maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.

51. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)].
52. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
53. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
54. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
55. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
56. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
57. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
58. Solid waste material viz., gutkha pouches, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
59. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
60. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, SEIAA, U.P. and UPPCB.
61. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at http://www.seiaaup.in and a copy of the same shall be forwarded to the Integrated Regional Office, MoEF&CC, GoI, Lucknow, CPCB, State PCB.
62. The MoEF&CC/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
63. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
64. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
65. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.

66. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along-with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. **The Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – soenvups@rediffmail.com)**
2. **Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi-Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)**
3. **Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)**
4. **Director, Geology & Mining, Uttar Pradesh, Khanij Bhawan 27/8, Raja Ram Mohan Rai Marg, Lucknow-226001 (email - dgmupexp@gmail.com)**
5. **District Magistrate, Fatehpur, Uttar Pradesh.**
6. **Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.com)**
7. **Copy to Web Master for uploading on PARIVESH Portal.**
8. **Copy for Guard File.**

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary, SEIAA

Signature Not Verified
Digitally signed by Member Secretary
Member Secretary
Date: 5/2/2022 6:26:47 PM

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

175629/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO)/CTO/both/FATEHPUR/2023 **Date: 16/02/2023**

To,

M/s

MS RB ENTERPRISES

Gata no- 64-586

Application Id-19510464

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **MS RB ENTERPRISES** located at **Gata no- 64-586**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA MS RB ENTERPRISES **granted for the period from 16/02/2023 to 31/12/2024** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	375000	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 375000 Cu meter/annum, by opencast and manual mining in 50 hectare leased area at Arazi No. 64 to 69, 83 to 91, 108 to 112, 115 to 121, 141 to 149, 161, 162, 167, 168, 183 to 186, 202 to 210, 234 to 245, 301 to 313, 383 to 390, 395 to 402, 409 to 412, 417 to 423, 463, 464, 587/471, 471 to 475, 499, 500, 505 to 510, 537 to 544, 561 to 565, 577 to 579, 585 & 586, Village- Urauli, Tehsil- Fatehpur, District-Fatehpur.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC22B001UP163690 dated 02.05.2022, and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement expires prior to 31-12-2024, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, MoEF&CC, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

RAJENDRA SINGH

Digitally signed by RAJENDRA SINGH
Date: 2023.02.16 16:42:07 +05'30'

Copy to:

Chief Environmental Officer (circle-2)

- Regional Officer, UPPCB, Banda with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis.

RAJENDRA SINGH Digitally signed by RAJENDRA SINGH
Date: 2023.02.16 16:42:19 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

संलग्नक- (4)

आदेश

मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर स्थित ग्राम उरौली के बालू/मोरम खण्ड सं0–उरौली की गाटा संख्या–64 से 69, 83 से 91तक, 108से 112तक, 115से 121तक, 141से 149तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423तक, 463, 464, 587/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586 कुल रकबा 50.00हे0 का खनन पट्टा दिनांक 07.05.2022 से 06.05.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

खनन पट्टा संचालन अवधि के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की जॉच विभिन्न तिथियों में की गयी। जॉच मे पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार नोटिस निर्गत की गई :–

तालिका–1

क्र	जॉच का दिनांक	जॉच के दौरान खनन क्षेत्र मे पायी गयी अनियमितता	जॉच आख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस का विवरण	पट्टाधारक द्वारा किये गये कृत्य के अनुसार नियम का उल्लंघन	उल्लंघन के अनुसार नोटिस मे निहित शास्ति/जुर्माना की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान मे आरोपित शास्ति व अन्य धनराशि
1	2	2	4	5	6
1.	27.12.2022	जॉच के दौरान 17 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक/बिना परिवहन प्रपत्र के पाये गये	पत्र सं0–16/30–खनिज (2022–2023) दिनांक 07.01.2023	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार नियमावली–2021 के नियम–60(6)	**4,25,000/–**
2.	28.02.2023	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लंघन है	पत्र सं0–211/ खनिज (2022–2023) दिनांक 28.03.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(4) का उल्लंघन है	**5,00,000/–**
3.	17.06.2023	स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 60X40X1=2400 घ0मी0 एवं 58X42X1=2436घ0मी0 कुल 4836घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किया गया, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58 व 72 का उल्लंघन है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर रास्ते मे कुल 06 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज परिवहन करते हुये पड़े गये, जिन पर एम–चेक के मायम से आनलाइन चालान किया गया। उक्त	कार्यालय पत्र सं0–456/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 27.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 व 60(6) का उल्लंघन है	रायल्टी एवं खनिज मूल्य **रु0–43,52,400/–** शास्ति **रु0–5,00,000/–** लोडिंग सन्नियों के उल्लंघन पर 06 वाहनों से **रु0–1,50,000/–**

		कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियम–60 (6) का उल्लंघन है			
4.	23.06.2023	01 पिलर गिरा हुआ पाया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ का अनुरक्षण नही किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है। 04 वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक उपखनिज का परिवहन करते हुये पाये गये, जो नियम–60 (6) का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–461/खनिज/2023/उरौली दिनांक 30.06.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–60 (3)व 60(6) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– लोडिंग सन्नियमों के उल्लंघन पर 04 वाहनों से रु0–1,00,000/–
5.	02.01.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा स्तम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1)का उल्लंघन है। पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नही पाया गया, जो उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–36(2) स्वीकृत क्षेत्र से बाहर कुल 113घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–461/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– पी0टी0जेड0 कैमरा क्रियाशील नही होने पर रु0–25,000/– रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–1,01,700/– शास्ति रु0–5,00,000/–
6.	10.02.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा सतम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 1000क्वायर मीटर मे 01 मीटर की गहराई मे कुल 1000घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया गया है, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–236/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–9,00,000/– शास्ति रु0–5,00,000/–
7.	21.02.2024	जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42(ज) का उल्लंघन है।	कार्यालय पत्र सं0–268/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60 (4) का उल्लंघन है	जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में रु0–5,00,000/–

8.	19.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र मे सीमा सतम्भ अनुरक्षित नही पाये गये, जो उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (1) का उल्लंघन है, जलस्तर आने के बाद भी खनन कार्य किये जाने से उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–436/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 60 (3) व (4) का उल्लंघन है	सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण नही करने पर रु0–25,000/– जलस्तर आने के उपरान्त खनन कार्य किये जाने के आरोप में रु0–5,00,000/–
9	30.03.2024	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल मात्रा 644.80 घ0मी0 बालू/मोरम का अवैध खनन किये जाने के कारण उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3, 58, 72 का उल्लंघन है	कार्यालय पत्र सं0–435/खनिज/ख0प0/उरौली 2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई	उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 3, 58, 72 का उल्लंघन है	रायल्टी एवं खनिज मूल्य रु0–5,80,320/– शास्ति रु0–5,00,000/–
				योग	1,02,34,420/–

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 (2) में यह प्राविधानित है कि "खनन पट्टा धारक जिसका खनन पट्टा क्षेत्र 05 हेक्टेयर से अधिक है, परिवहन के निगरानी के लिए, स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा जिससे सम्बन्धित खनन पट्टाकृत क्षेत्र के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप मे अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिन तक रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन यथा उपबन्धित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध करायेगा।"

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–42 (ज)(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टेदार नदी तल मे तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर जो भी कम हो, के परे कोई खनन संक्रियायें नहीं करेगा और कोई खनन, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे परीक्षण किये गये सुरक्षा क्षेत्र मे नही किया जायेगा : प्रतिबन्ध यह है कि कोई खनन, जलधारा मे सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि की सहायता से नही किया जायेगा।"

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(4) में यह प्राविधानित है कि "नियम 42 (ज) के अधीन उपबन्धित उपबन्धों के अनुसार जल धारा मे सक्शन मशीन/लिफ्टर के माध्यम से खनन कार्य निषिद्ध होगा। यदि कोई पट्टाधारक उक्त नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रत्येक अवसर पर पॉच लाख रूपये की दर से शास्ति के लिए दायी होगा, जो जिला मजिस्ट्रेट या निदेशक के आदेश पर वसूला जायेगा। शास्ति की उपरोक्त उल्लिखित धनराशि को जमा करने मे विफल होने पर उस धनराशि को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36(1) में यह प्राविधानित है कि "पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र के सीमांकन मानचित्र पर कोर्डिनेटस चिन्हांकित किये जायेंगे तथा पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमांचिन्ह को और खम्भे को परिनिर्मित करेगा और सदैव अनुरक्षित करेगा और अच्छी स्थिति मे रखेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे मे दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक हो"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–60(3) में यह प्राविधानित है कि "यदि पट्टाधारक, नियम 36 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक चूक के लिए प्रतिदिन पच्चीस हजार रूपये की दर से शास्ति, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उद्गृहीत की जायेगी। ऐसी उद्गृहीत शास्ति को जमा करने पर चूक की दशा मे उक्त धनराशि की कटौती संबंधित जिला मजिस्ट्रेट उक्त खनन पट्टा के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से करेगा"।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–3 में यह प्राविधानित है कि "कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र मे किसी ऐसे उपखनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की निबन्धन और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियाएं नही कर सकेगा।"

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–58 में यह प्राविधानित है कि "जो कोई नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों मे से किसी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पॉच वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अन्यून दो लाख रूपये एवं अधिकतम पॉच लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।"

उक्त तालिका के क्रमांक 01 लगायत 09 मे उल्लिखित जॉच आख्याओं के क्रम में निर्गत नोटिसों में से मात्र क्रमांक 03 मे उल्लिखित कार्यालय पत्र सं0–456/ खनिज/2023/उरौली दिनांक 27.06.2023 का उत्तर निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :–

नोटिस सं0–456 दिनांक 27.06.2023 के जवाब मे उल्लिखित किया गया है कि *"प्रार्थी का क्षेत्र 50हे0 का है और प्रत्येक वर्ष 3,75,000घ0मी0 मोरम का खनन किये जाने हेतु दिया गया है। प्रार्थी के क्षेत्र मे मिट्टी मिली हुई बोग्दा बालू लगभग 1.00 से 1.5 मीटर की गहराई तक है, जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है, प्रार्थी उसको हटाकर खनन करता है, खराब क्वालिटी की मोरम को क्षेत्र मे ही ढेर के रूप मे एकत्रित करना पड़ता है, कहीं–कहीं स्वीकृत क्षेत्र के किनारों के पास जब खनन किया जाता है तो खराब क्वालिटी की मोरम को क्षेत्र के बाहर भी खदान मे कार्यरत कर्मचारियों द्वारा डाल दिया गया है। प्रार्थी ने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर मोरम का अवैध खनन नही किया गया है, टीम द्वारा क्षेत्र के बाहर पड़े हुये ओवरबर्डन को अवैध खनन बता दिया गया है। दिनांक 17.06.2023 की जॉच मे प्रार्थी खनन पट्टा क्षेत्र मे उपस्थित भी नही था, यदि प्रार्थी उपस्थित होता तो सारे तथ्यों से टीम को अवगत कराता, हम लोगों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन नही किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र मे ही खनन कार्य किया गया है, जिसकी पूर्व मे जॉच से स्पष्ट है। जॉच के समय पट्टाधारक/प्रतिनिधि के रूप मे कोई मौके पर उपस्थित नही था, हमारे क्षेत्र मे ओवरबर्डन की मात्रा अधिक है तथा ओवरबर्डन को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रखा गया था, जिसे जॉच टीम द्वारा अवैध खनन माना गया है। जॉच टीम को अवैध खनन के कोई गड्ढे नही मिले हैं ओवर बर्डन को देखकर अनुमान लगाया गया है। मौके पर हमारे रहने से उसकी यथास्थिति से टीम को अवगत कराया जाता, परन्तु नही रहने से टीम को यथास्थिति से अवगत न होने के कारण टीम द्वारा अवैध खनन बताया जा रहा है। जॉच टीम द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किस दिशा मे अवैध खनन पाया गया, इसका भी वर्णन नही है। क्योंकि क्षेत्र मे स्वीकृत एरिया से बाहर हर जगह ओवरबर्डन है ऐसी स्थिति में ओवरबर्डन को अवैध खनन कहना सही नही है। उक्त की जॉच हमारे उपस्थित मे पुनः की जा सकती है। जॉच टीम द्वारा 06 वाहन ओवरलोड होना बताया गया है, परन्तु उक्त वाहनों का विवरण नही है, जिससे अपने डाटा से चेक करने मे परेशानी हो रही है। उक्त वाहनों पर हमारे यहॉ के परिवहन प्रपत्र पाये गये है तो उसका विवरण देने का कष्ट करें, जिससे मै सही स्थिति से अवगत करा सकूँ। बोर्ड व पिलर लगा हुआ है, क्षेत्र का पिलर मौके पर ही गिर गया था, जो जॉच टीम द्वारा पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि हमलोगों द्वारा पिलर लगाया हुआ था, आधी–तूफान मे गिरने से उसे लगा हुआ नही लिखना न्यायोचित नही है।*

उक्त उत्तर के अन्त में जनपद स्तर की टीम के साथ आवश्यक रूप से निदेशाल के तकनीकी अधिकारियों की एक टीम बनावाकर प्रार्थी की उपस्थित मे खण्ड की सही ढंग से दुबारा जॉच कराये जाने का अनुरोध किया गया है।"

पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उत्तर/स्पष्टीकरण का अवलोकन/परिशीलन किया गया, पट्टाधारक का मुख्य कथन कि 'खनन पट्टा क्षेत्र मे अवैध खनन नही किया गया है, टीम द्वारा ओवरबर्डन को ही अवैध खनन के रूप मे नाप कर अवैध खनन लगाया गया है, यह तथ्य मान्य नही है, क्योंकि उक्त जॉच दिनांक 17.06.2023 मे जनपदीय खान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज एवं उप जिलाधिकारी सदर सम्मिलित थे, खान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज खनन क्षेत्र मे हुये अवैध खनन एवं रखे गये ओवरबर्डन पर स्पष्ट अन्तर देखने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। उक्त जॉच दिनांक को पकड़े गये अवैध खनन की कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से पट्टाधारक द्वारा ओवरबर्डन का सहारा लेकर क्षेत्र की पुनः जॉच की मॉग मानसून सत्र मे की गई है, जो मान्य नही है। साथ ही उक्त खनन क्षेत्र के रास्ते मे ही बिना परिवहन प्रपत्र के वाहन पकड़े गये थे, इसमे पट्टाधारक यह कथन कि वाहनों का विवरण उपलब्ध नही कराया गया है, तथ्यहीन है। उक्तानुसार पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण तथ्यहीन/साक्ष्यहीन/संतोषजनक नही होने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किया गया है।

उपरोक्त नियमों का उल्लंघन किये जाने के क्रम में क्रमांक–3 मे उल्लिखित नोटिस के अतिरिक्त निर्गत अन्य 08 नोटिसों का पट्टाधारक द्वारा कोई जवाब/उत्तर प्रस्तुत नही किया गया और न ही नोटिस मे उल्लिखित शास्ति/जुर्माना/रायल्टी/खनिज मूल्य जमा किया गया है।

उक्त खनन पट्टा के सम्बन्ध मे पट्टाधारक द्वारा माह अप्रैल, 2024 मे देय निर्धारित किश्त रु0–78,78,750/– के सापेक्ष मात्र रु0–9,32,425/– जमा किया गया है, माह अप्रैल की देय किश्त मे कुल रु0–69,46,325/– जमा किया जाना शेष है। माह मई, 2024 मे देय तृतीय वर्ष की प्रथम किश्त (20 प्रतिशत) की धनराशि रु0–1,73,33,250/– की देयता बन गई है, परन्तु पट्टाधारक द्वारा किश्त की धनराशि जमा नही की गई है। खनन पट्टा अनुबन्ध मे अंकित पंचम अनुसूची के अनुसार माह की प्रथम तारीख को देय मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करना होता है, देय किश्तों की बकाया धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

तालिका–2

माह	देय किश्त की धनराशि	जमा किश्त की धनराशि	**किश्त की अवशेष बकाया धनराशि**
1	2	3	**4**
अप्रैल, 2024	78,78,750/–	9,32,425/–	69,46,325/–
मई, 2024	1,73,33,250/–	––	1,73,33,250/–
योग	**2,52,12,000/–**	**9,32,425/–**	**2,42,79,575/–**

कार्यालय पत्र सं0–1080/30–खनिज (2022–2023) दिनांक 27.07.2022 एवं कार्यालय पत्र सं0–322/खनिज/डी0एम0एफ0–टी0सी0एस0/2023 दिनांक 10.05.2023 द्वारा समय–समय पर डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की बकाया धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु पट्टाधारक द्वारा धनराशि जमा नही की गई। माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक निम्न विवरण के अनुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 की देयता बनती है :–

तालिका–3

क्र0	मद	विवरण	बकाया धनराशि
1.	डी0एम0एफ0	माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक	**1,67,74,575/–**
2.	टी0सी0एस0	माह मई, 2022 से माह मई, 2024 तक	**33,54,915/–**

यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार आनलाइन नोटिस निर्गत की गई है, जिसके सम्बन्ध मे आप द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गई और न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है, का विवरण निम्नवत् है :-

तालिका-4

क्र0	मद	विवरण				
		लीज आई डी	वाल्यूम मिसमैच नोटिसों की संख्या	बिदआउट ई-एम0एम0-11 नोटिसों की संख्या	वाल्यूम मिसमैच नोटिसों की बकाया धनराशि	बिदआउट ई-एम0एम0-11 नोटिसों की बकाया धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल पर वाल्यूम मिसमैच एव बिद आउट ई-एम0एम0-11 के आनलाइन नोटिस	314322070126	25	143	1,07,793/-	38,50,000/-
		314323070179	12	401	73,530/-	1,00,75,000/-
		योग	37	544	1,81,323/-	1,39,25,000/-
				कुल योग (कालम नम्बर-6 व 7)	1,41,06,323/-	

उपरोक्तानुसार मोरम खण्ड सं0-उरौली में उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के उक्त नियमों एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उपरोक्त तालिका-1, 2, 3 व 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि की देयता बनती है।

पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत उत्तर/स्पष्टीकरण को खारिज करते हुये उपरोक्त बकाया धनराशि को जमा करने हेतु कार्यालय पत्र सं0-706/खनिज/ख0प0/आर0बी0/2024 दिनांक 22.05.2024 के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये कारण बताओ नोटिस निर्गत की गई, परन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पट्टाधारक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया गया और न ही बकाया धनराशि ही जमा नही की गई।

मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता-अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा पट्टाधारक मोरम खण्ड सं0-उरौली के द्वारा उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली-2021 के उक्त नियमों एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण उपरोक्त तालिका-1, 2, 3 व 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार धनराशि की देयता बनी है। पट्टाधारक का यह कृत्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-42(ज), 60(6), 3, 58, 72, 36(1), (2) एवं खनन पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 मे प्रदत्त अधिकारों के तहत मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता-अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा के पक्ष में स्वीकृत खनन उपरोक्त बालू/मोरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं बकाया धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध मे निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं :-

1. तालिका-1 मे उल्लिखित शास्ति सहित कुल बकाया धनराशि रू0-1,02,34,420/-, तालिका-2 में उल्लिखित खनन पट्टा किश्त की बकाया धनराशि रू0-2,42,79,575/- तालिका-4 मे उल्लिखित यू0पी0एम0डी0एस0एस0 पोर्टल पर वाल्यूम मिसमैच एवं बिद आउट ई-एम0एम0-11 के आनलाइन नोटिस की धनराशि रू0-1,41,06,323/- कुल धनराशि रू0-4,86,20,318/- को जमा प्रतिभूति की धनराशि 1,79,06,250/- मे समायोजित किया जाता है। पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि समायोजन के उपरान्त अवशेष बकाया धनराशि रू0-3,07,14,068/-आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक "0853"/राजकोष के एकवी कोड के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति खनिज कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

73 डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रु0–1,67,74,575/– जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास फतेहपुर के खाता संख्या–37171070081 आई0एफ0एस0सी0 कोड–SBIN0000076 मे, तथा देय टी0सी0एस0 की धनराशि रु0–रु0–33,54,915/– को निर्धारित टैन नं0–ALDD00887F में) आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर जमा कराकर जमा रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य कोई देयता बनती है, तो उसकी वसूली पृथक से की जायेगी।

3. पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त अधिरोपित धनराशि नियत समय मे जमा नही करने पर नियमानुसार बकाया धनराशि की वसूली समस्त भागीदारों से भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूल किये जाने हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति सम्बन्धित को पंजीकृत डाक/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाये।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1054/खनिज/ख0प0/उरौली/2024 दिनांक 11/07/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खनिज फतेहपुर।
5. मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज, कार्यालय पता–अर्तरा चुंगी चौकी, कुशवाहा नगर जिला बॉदा, पार्टनर श्री बीरेंन्द्र सिंह पुत्र श्री राम किशोर सिंह निवासी अतर्रा चुंगी, शास्त्री नगर थाना कोतवाली, बॉदा।

10/7/24

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

संलग्नक-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H118875

Ref. No .... / सी-2/वायु-356/24

दिनाँक
Date 31-10-24

2 बजे 5 बजे 8 बजे

सेवा मे,

मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज
गाटा सं० 64-586, ग्राम उरौली, तहसील-फतेहपुर,
जनपद-फतेहपुर।

विषय- मेसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, गाटा सं० 64-586, ग्राम उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल/वायु आदेश दिनांक 16.02.2023 को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 00997/आर-204/2024 दिनांक 17.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि जिलाधिकारी, फतेहपुर के आदेश संख्या 1054/खनिज/ख०प०/उरौली/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा मैसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर द्वारा पार्टनर श्री बिरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशोर सिंह, निवासी अतर्रा, चुंगी, शास्त्री नगर, थाना-कोतवाली, बांदा के पक्ष में स्वीकृत बालू/मौरम खनन पट्टा क्षेत्र उरौली को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निरस्त किया गया है।

आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट Ref No. 175629/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO) /CTO/both/Fatehpur/2023 dated 16-02-2023 बालू खनन हेतु दिनांक 31.12.2024 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था। उक्त सहमति आदेश में अधिरोपित विशिष्ट शर्त संख्या-03 निम्नानुसार है -

"..... 3. If the lease agreement expired prior to 31.12.2024, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease......"

खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से खनन पटटा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.10.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 को रिवोक/खण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स आर०बी० इण्टरप्राइजेज, ग्राम-उरौली, तहसील-फतेहपुर, जनपद-फतेहपुर को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 16.02.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया जाता है तथा उक्त स्थल पर लीज आवंटन के सम्बंध में भविष्य में कोई आदेश जारी होने पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थल पर बिना पूर्व अनुमति के खनन कार्य न किया जाये।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - (6)

ओ0ए0 नं0 959/2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के अनुपालन में निरीक्षण दिनांक 16.10.2024 के समय लिये गये फोटोग्राफ्स